

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

# उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

# असाधारण

## विधायी परिशिष्ट

भाग<sub>-1</sub>, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

## लखनऊ, सोमवार, 6 मार्च, 2023

फाल्गुन 15, 1944 शक सम्वत्

### उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग–1

संख्या 97 / 79-वि-1—2023-1-क-2-2023 लखनऊ, 6 मार्च, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2023 जिससे संसदीय कार्य अनुभाग—1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 3 मार्च, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2023 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन)

(संशोधन) अधिनियम, 2023

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2023) [जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

#### अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की संक्षिप्त नाम व उपलिब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जायेगा।

(2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 1980 की धारा 26—क का संशोधन 2—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 की धारा 26—क में, उपधारा (1) तथा उपधारा (2) में, शब्द "दस हजार" के स्थान पर शब्द "पच्चीस हजार" रख दिये जायेंगे;

## उद्देश्य और कारण

राज्य विधान मण्डल के सदस्यों को वेतन, भत्तों का भुगतान तथा अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित विधि को समेकित एवं संशोधित किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) अधिनियम, 1980 अधिनियमित किया गया है।

पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन राज्य विधान मण्डल के किसी भी सदन के भूतपूर्व सदस्य पेंशन तथा अन्य प्रसुविधाएं प्राप्त करने के हकदार हैं। पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 26-क की उपधारा (2) के अधीन मृत भृतपूर्व सदस्यों के पति / पत्नियाँ भी पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2016 के माध्यम से पूर्वीक्त अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) को संशोधित करके भूतपूर्व सदस्यों के लिए अनुमन्य पेंशन को दस हजार रुपये से बढ़ाकर पच्चीस हजार रुपये कर दिया गया। अतएव उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियाँ और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रारम्भ होने के दिनांक अर्थात दिनांक 11 सितम्बर, 2016 के पश्चात् मृत भूतपूर्व सदस्यों के पति / पत्नियाँ, न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये पेंशन अथवा मृत भूतपूर्व सदस्य को अन्यथा अनुमन्य पेंशन, जो भी अधिक हो, के लिए हकदार हैं। किन्तु पूर्वोक्त अधिनियम, 2016 के प्रारम्भ होने से पूर्व मृत भृतपूर्व सदस्यों के पित / पित्नयों की पारिवारिक पेंशन, पूर्वीक्त अधिनियम की धारा 26-क की उपधारा (2) के उपबंध के अनुसार अधिकतम दस हजार रुपये अथवा मृत भृतपूर्व सदस्य को अन्यथा अनुमन्य सीमा तक सीमित है। अतएव ऐसे पति / पत्नियाँ, दिनांक 11 सितम्बर, 2016 के पश्चात मृत भृतपूर्व सदस्यों के पति / पत्नियों की तूलना में बहुत कम पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे / रही हैं। इस विसंगति को दूर करने और ऐसे पति / पत्नियों को पच्चीस हजार रुपये न्यूनतम पारिवारिक पेंशन की प्रस्विधा प्रदान किये जाने का उपबंध करने के लिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन किये जाने का विनिश्चय किया गया है।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलक्ष्यियाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2023 पुरःस्थापित किया जाता है।

> आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।

#### No. 97(2)/LXXIX-V-1-2023-1-ka-2-2023

Dated Lucknow, March 6, 2023

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vidhan Mandal (Sadasyon Ki Uplabdhiyan Aur Pension) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2023 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 2 of 2023) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 3, 2023. The Sansadiya Karya Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

# THE UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE (MEMBERS' EMOLUMENTS AND PENSION) (AMENDMENT) ACT, 2023

(U.P. Act no. 2 of 2023)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980 .

IT IS HEREBY enacted in the Seventy fourth Year of Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2023.

Short title and commencement

- (2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Gazette.
- 2. (1) In section 26-A of the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980, in sub-sections (1) and (2) *for* the words "ten thousand" the words "twenty five thousand" shall be *substituted*.

Amendment of section 26-A of U.P. Act no. 23 of 1980

#### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) Act, 1980 has been enacted to consolidate and amend the law relating to payment of salaries, allowances and other facilities to the members of the State Legislature.

Under the aforesaid Act, the *ex-members* of either house of State Legislature are entitled to get pension and other benefits. The spouses of deceased *ex-members* are also entitled to get family pension under sub-section (2) of section 26-A of the aforesaid Act. Through the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2016, the pension admissible to *ex-members* was raised from rupees ten thousand to rupees twenty five thousand by amending the sub-section (1) of section 24 of the aforesaid Act. Therefore the spouses of those *ex-members* who expired after the commencement of the Uttar Pradesh State Legislature (Members' Emoluments and Pension) (Amendment) Act, 2016 *i.e.*, September 11, 2016, are entitled to a minimum pension of rupees twenty five thousand or pension otherwise admissible to the deceased *ex-member*, whichever is greater. But the family pension of spouses of those *ex-members* who expired before the commencement of the aforesaid Act of 2016 is confined to a maximum limit of rupees ten thousand or pension as otherwise admissible to the dues *ex-members* as per the provision of sub-section (2) of section 26-A of the aforesaid Act. Therefore such spouses are getting

much less family pension as compared to spouses of those *ex-members* who expired after September 11, 2016. To remove this discrepancy and to provide for giving the benefit of a minimum family pension of rupees twenty five thousand to such spouses, it has been decided to amend the aforesaid Act.

The Uttar Pradesh State Legislature (Members Emoluments and Pension) (Amendment) Bill, 2023 is introduced accordingly.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.